नगर आवासीय संगठनों संबंधी कृतिक बल समिति की सिफारिशें

2380. श्रीमती किशोरी सिंहा :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
डा० सुब्रहमण्यम स्वामी :
श्री अरुण कुमार नेहरू :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में कार्यरत आवासीय संगठनों के कार्यकरण को देखने के लिए एक कृतिक बल समिति नियुक्त की थी और उससे अध्ययन के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन मे इस संगठनों के पुनर्गठन के लिए कोई सिफारिशें की गई हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में आवासीय संगठनों के कार्यकलापों की ओर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए ही कृतिक बल की स्थापना नहीं की है। तथापि शहरी गरीबों को आश्रय देने और गंदी बस्तियों को सुधारने से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए जनवरी, 1983 में एक कृतिक बल की स्थापना की गई थी। इस कृतिक बल ने अपने निष्कर्षों और सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण दि० 27 सितंबर, 1983 को प्रस्तुत किया।

(ग) कृतिक बल ने शहरी क्षेत्रों में आवासीय संगठनों को पुन: स्थापित करने के लिए विशिष्ट सिफारिस नहीं की है। फिर भी, इसने शहरी गरीबों के पक्ष में आवासीय कार्यकलापों में कार्यरत सभी सार्वजनिक अभिकरणों के पूर्वाभिकरण का सुझाव दिया है। इसने यह भी सुझाव दिया है कि इन संगठनों को भूमि के विकास और आधार संरचना का संकेन्द्रण करना चाहिए और अपने आवासीय निर्माण कार्यक्रमों में न्यूनतम कमी करनी चाहिए।

Ban on Hunting of Wildlife

2381. SHRI R.P. GAEKWAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that bans imposed by State on hunting of wild life have not proved effective since the States have no machinery for enforcement of these methods ; and

(b) steps Government propose to take for proper preservation of wild life and proper game management ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (SHRI DIGVIJAY SINH) ; (a) Under the Wild Life (Protection) Act, 1972, the State Governments are fully competent to impose ban on hunting of wildlife. The States which have imposed any such ban are taking action to enforce it. However, cases of poachingdo occur and are being detected and dealt with at the State level. The Central Government has been advising all the State Governments to strengthen the enforcement machinery for this purpose and to deal with cases of poaching strictly.

(b) A statement is attached.

Statement

Some of the important measures taken in recent years for wildlife con-